clared dangerous; if so, the reasons for repairing their staircases only;

(b) whether the CPWD has refunded the maintenance grant of its H-Division, while a lot of maintenance works remain to be carried out;

(c) whether the water supply timings of J-Block have been changed suddenly; if so, whether old timings would be restored;

(d) whether despite approval of the construction of boundary wall of J-Block, the work is still in suspense; and

(e) the reasons for calling tenders of white-wash only just before one week of "Diwali"?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) No, Sir. Repair of staircases has been taken up in the first phase and the works are in progress. Subject to availability of funds, repair of balconies and other parts of these quarters would be taken up in the second phase.

(b) No, Sir.

(c) Timings have been changed to supply water to all the blocks at the same time from the newly constructed overhead tank. Earlier, water supply to different blocks was staggerred.

(d) Construction of the boundary wall has not been sanctioned so far.

(e) Tenders for white-wash are called after the monsoons and works carried out upto the end of the financial year.

Cost-Benefit Study on mode of LPG Supply

1833. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any cost-benefit study on the comparative advantages of supply of LPG for domestic use through cylinders and through a piped system;

(b) if so, when was this cost-benefit study done;

(c) the organisation which carried out this study;

(d) whether any town or urban areas has been studied in Andhra Pradesh under this cost-benefit survey; and

(e) if so, the details of such a study conducted in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (e) Govt. Oil Companies have examined the feasibility of supply of LPG to the consumers through pipeline in new housing colonies. The international consulting firms have advised to use proper rich LPG (minimum 80% of propane) on overall technological and safety considerations. The initial investment cost of providing LPG per household would be in the range of Rs. 50,000/- to Rs. 85,000/- depending on the design and lay-out. This high cost will have to be passed on to the consumers. It also involves transfer of bulk LPG from the LPG tank truck to the bulk storage facility in the residential area.

Considering the safety and economic considerations, it is found that supply of LPG by pipeline is not feasible in Indian conditions.

पूर्वोत्तर क्षेत्र और राजस्थान में रोजगार

1834. **श्री पराग चालिहा:**
श्री शिव चरण सिंह:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र और राजस्थान के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए कोई विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा): (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसे मुख्य रोजगार कार्यक्रम हैं, जिन्हें उत्तर पूर्वी राज्यों एवं राजस्थान राज्य के आदिवासी इलाकों सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए 1994 में सचिवों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति के विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया था कि बैंक रहित विकास खंडों में ऋण को सबसिडी से अलग किया जाए क्योंकि लाभार्थियों एवं समुदाय द्वारा समान अंश में योगदान किया गया था। उत्तर पूर्वी राज्यों की विशेष समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, उत्तर पूर्वी राज्यों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां एक ही किस्त में रिलीज की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुवर्तन में, उत्तर पूर्वी राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास संबंधी आबंटन को कुल आबंटन के 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

1835. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला-वार उन गांवों/उप-गांवों के नाम क्या हैं, जिनके इस वर्ष विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृति दी गई है और जिला-वार किन-किन गांवों/उपगांवों में यह कार्य चल रहा है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम "सिस्टम इम्प्रूवमेंट स्कीम" के तहत ब्लाक-वार कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) हिमाचल प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार जितने भी गांव विद्युतीकरण की दृष्टि से व्यावहारिक थे, सबको पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है। जहां तक उप-गांवों (हेमलेट) का संबंध है, वर्ष 1996-97 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजलीबोर्ड (एच०पी०एस०बी०) ने बताया कि अप्रैल-जून 1996 की अवधि के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित स्कीम के अंतर्गत 34 हेमलेटों का विद्युतीकरण किया गया। इन हेमलेटों का जिलेवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (*नीचे देखिए*)

(ख) मानदंडों के अनुरूप खण्ड-वार प्रणाली सुधार किए जाने के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास हिमाचल प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) भाग (ख) में दिए गए उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान जून, 96 तक विद्युतीकृत किए गए हेमलेट:

क्र० सं०	हेमलेट का नाम	जिला
1.	कुकरी	कुल्लु
2.	लमसाई	सोलन
3.	शोगी	"
4.	सुराब बैरेक	"
5.	मंघाई	"
6.	दोची शीशी	"
7.	दोची बट्टू	"
8.	चैहम	"
9.	कुआली	"
10.	मदहर	शिमला
11.	कयात्ती	"
12.	थारू	"
13.	कंगरंग	किन्नौर
14.	रवाई	"
15.	दहाया	"
16.	टंगलिंग	"
17.	कलिंगंग	"
18.	हुरी	"
19.	नमपो	"